




All India Bar Examination-IX [2016]

SR. No.	Subjects	Questions No.	Total No. of Q.	Marks	Weightage (%)
1	Constitution of India	3,4,5,18,19,36,42	7	7	7%
2	Indian Penal code	13,16,24,46,64,66	6	6	6%
3	Civil Procedure Code	8,9,20,21,22	5	5	5%
4	Criminal Procedure Code	54,65,72,73,74,75,76,85,86,87	10	10	10%
5	Indian Evidence Act	51,52,53,70,71,81,82,83,84	9	9	9%
6	Arbitration & Conciliation Act	1,30,33,100	4	4	4%
7	Professional Ethics & Cases of Professional Misconduct Under Bar Council of India Rules	29,43,44,99	4	4	4%
8	Family Law	27,97	2	2	2%
9	Company Law	15,17,31,34,96	5	5	5%
10	Environment Pro. Act	6,7,32,35	4	4	4%
11	Cyber Law	2,23,61,62,63,78	6	6	6%
12	Labour & Industrial Law	25,26,39,47,48,67	6	6	6%
13	Law Of Torts, M.V. Act and Consumer Protection Law	40,49,50,68,69,79,80	7	7	7%
14	Law of Contract, Specific Relief, Property Laws, Negotiable Instrument Act,	14,38,55,56,57,58,59,77,88,89,90,91,92,93,94,98	16	16	16%
15	Limitation Act	45,95	2	2	2%
16	International Law	10,11,12,60	4	4	4%
17	Jurisprudence	28,41	2	2	2%
18	GK	37	1	1	1%
Total			100	100	100%

Questions Paper with Linked provision is available on Linking App (Only for Paid Users)



Scan this QR Code to Linking Laws BLOs

 Linking Laws
 Linking Laws Tansukh Sir
 www.LinkingLaws.com
 Get Subscription Now

Linking Laws is a Professional Institute provide
 AI based Smart Preparation for
 Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India
 (UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)



Constitution of India

3. Directive Principles are- / निर्देशक तत्व हैं -

- (1) justifiable as fundamental rights / मौलिक अधिकारों के रूप में न्यायोचित माने जाते हैं
- (2) justifiable but not as fundamental rights / न्यायोचित तो हैं लेकिन मौलिक अधिकार नहीं
- (3) decorative portions of Indian Constitution / भारतीय संविधान के सजावटी हिस्से हैं
- (4) not justifiable, yet fundamental in the governance of the country / न्यायोचित नहीं है, फिर भी देश के शासन के मूल अंग हैं।

Ans. [4]

4. Who has the power to dissolve the Lok Sabha / लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है

- (1) President/ राष्ट्रपति
- (2) Prime Minister/ प्रधानमंत्री
- (3) Speaker of Lok Sabha / लोक सभा अध्यक्ष
- (4) Council of Ministers / मंत्रिपरिषद

Ans. [1]

5. An amendment of the Constitution can be initiated by introduction of Bill for such purpose in/ संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के लिए, इस तरह के प्रयोजन के संबंध में विधेयक प्रस्तावित किया जा सकता है

- (1) Council of States/ राज्यसभा में
- (2) House of People / लोकसभा में
- (3) either in Council of States or House of People/ राज्यसभा या फिर लोकसभा में
- (4) none of the above / उपरोक्त में से कोई नहीं।

Ans. [3]

18. Which of the following are included in the concept of "State" under Article 12?/ अनुच्छेद 12 के अंतर्गत 'राज्य' की अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल किया गया है

- (1) Railway Board and Electricity Board/ रेलवे मंडल और विद्युत मंडल प्रश्न
- (2) Judiciary / न्यायपालिका
- (3) University / विश्वविद्यालय
- (4) All of the above / उपरोक्त सभी।

Ans. [2]

19. The word 'procedure established by law' in Article 21 means / अनुच्छेद 21 में 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' शब्द का आशय है-

- (1) that due process of law must be followed/ कानून द्वारा उल्लेखित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए
- (2) A procedure laid down or enacted by a competent authority / एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियमित या निर्धारित प्रक्रिया

- (3) The same thing as due process of law / कानून की उचित प्रक्रिया के समान ही बात हैं
- (4) A law which is reasonable, just and fair./ एक कानून, जो कि उचित, न्यायोचित और निष्पक्ष है।

Ans. [2]

36. The entry on forests and protection of Wild animals and birds was moved from..... to the..... by the 42nd Amendment to the Constitution of India. / भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के माध्यम से वन और वन्य जीवों और पक्षियों के संरक्षण के विषय को से... में स्थापित किया गया

- (1) Centre list to State list / केंद्रीय सूची से राज्य सूची
- (2) Centre list to Concurrent list / केंद्रीय सूची से समवर्ती सूची
- (3) State list to Concurrent list / राज्य सूची से समवर्ती सूची
- (4) State list to Union list / राज्य सूची से संघीय सूची

Ans. [3]

42. Which of the following is true in respect of a Government contract which does not confirm to provisions of Article 299 of the Constitution? / सरकारी संविदा के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है जो संविधान के अनुच्छेद 299 के प्रावधानों की पुष्टि नहीं करता है ?

- (1) They are not enforceable in Court against the parties/ वे पक्षों के खिलाफ न्यायलय में लागू करने योग्य नहीं हैं।
- (2) They can be rectified by the Government / उन्हें सरकार द्वारा ठीक जा सकता है।
- (3) Both (1) and (2) / (1) और (2) दोनों
- (4) Neither (1) nor (2) / ना ही (1) ना ही (2)

Ans. [1]

Indian Penal code

13. The committee that led to the passing of the Criminal Law Amendment Act, 2013 was headed by- / आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013 को पारित करने के समिति जो कि गठित की गई थी, उस के प्रमुख कौन थे

- (1) Justice Dalveer Bhandari / न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी
- (2) Justice Altamas Kabeer / न्यायमूर्ति अलतमस कबीर
- (3) Justice J.S. Verma / न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा
- (4) Justice J.S. Anand / न्यायमूर्ति जे. एस. आनंद

Ans. [3]

16. According to one of the theories of punishment evil should be returned by evil. This theory is called the / सजा के एक सिद्धांत के अनुसार बुराई को बदला बुराई से ही मिलना चाहिए। इस सिद्धांत को कहा जाता है।

- (1) Reformatory Theory / सुधारात्मक सिद्धांत
- (2) Deterrent Theory / बचाने वाला सिद्धांत
- (3) Preventive Theory / निरोधक सिद्धांत
- (4) Retributive Theory / दंड देने वाला सिद्धांत

Ans. [4]

Questions Paper with Linked provision is available on Linking App (Only for Paid Users)



Scan this
QR Code to
Linking Laws B10s

Linking Laws
Linking Laws Tansukh Sir
www.LinkingLaws.com
Get Subscription Now

Linking Laws is a Professional Institute provide
AI based Smart Preparation for
Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India
(UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)



24. The right to private defence is / निजी रक्षा करने का अधिकार

- (1) available under all circumstances / सभी परिस्थितियों के तहत उपलब्ध है
- (2) available when there is time to have the recourse to the protection of public authorities / उपलब्ध है, जब सरकारी अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त करने का समय है
- (3) available when there is no time to have recourse of public authorities/ उपलब्ध है जब वहाँ सरकारी अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त करने का कोई समय नहीं है
- (4) All the above / उपर्युक्त सभी।

Ans. [3]

46. To establish section 34 -/ धारा 34 स्थापित करने के लिए -

- (1) Common Intention must be proved but not overt act is required to be proved. / साझा आशय सिद्ध किया जाना चाहिए, लेकिन प्रत्यक्ष इरादा साबित किया जाना आवश्यक नहीं है
- (2) Common intention and overt act both are required to be proved / साझा आशय और प्रकट कृत्य दोनों साबित किया जाने की आवश्यकता है
- (3) Common intention need not be proved but only overt act is required to be proved. / साझा आशय सिद्ध किए जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रकट कृत्य साबित किया जाना आवश्यक है।
- (4) All of the above / उपरोक्त सभी

Ans. [2]

64. In the light of the Criminal Law Amendment Act, 2013, which of the following Statement is lare correct?/ आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013 के प्रकाश में निम्नलिखित में से कौन कथन सही हैं ?

- (1) The word "rape" in Section 375 of Indian Penal Code, 1860 has been replaced with sexual assault / भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 375 में शब्द 'बलात्कार' को यौन उत्पीड़न के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है
- (2) Rape is now a gender-neutral offence / बलात्कार अब एक लिंग तटस्थ अपराध है
- (3) The amendment has fixed the age for consensual sex as 16 years / संशोधन के तहत आम सहमति से सेक्स के लिए उम्र 16 साल तय की गई है
- (4) All the above / उपर्युक्त सभी।

Ans. [Grace]

66. In kidnapping, the consent of minor is/ अपहरण में नाबालिग की सहमति

- (1) wholly immaterial / पूर्णतः अर्थहीन है
- (2) partly immaterial / आंशिक रूप से अर्थहीन है
- (3) wholly material / पूर्णतः अर्थपूर्ण है
- (4) partly material / आंशिक रूप से अर्थपूर्ण है।

Ans. [1]

Civil Procedure Code

8. Section 10 of CPC does not apply-/ सीपीसी की धारा 10 लागू नहीं होती

- (1) when the previous suit is pending in the same Court / जब पूर्व का वाद उसी न्यायलय में लंबित हो
- (2) when the previous suit is pending in a foreign Court / जब पूर्व का वाद किसी विदेशी न्यायलय में लंबित हो
- (3) when the previous suit is pending in any other Court of India./ जब पूर्व का वाद भारत की किसी अन्य न्यायलय में लंबित हो
- (4) when the previous suit is pending in a Court outside India established by the Central Government / जब पूर्व का वाद भारत के बाहर, केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित न्यायलय में लंबित हो।

Ans. [2]

9. Principle of Res judicata is / पूर्वन्याय का सिद्धांत है

- (1) Mandatory / अनिवार्य
- (2) Directory / निर्देशिका
- (3) Discretionary / विवेकाधीन
- (4) All the above / उपर्युक्त सभी।

Ans. [1]

20. Objection as to non-joinder or mis-joinder of parties under Order 1, Rule 13 of CPC / सीपीसी के नियम 13, आदेश 1 के तहत पक्षकारों के असंयोजन या कु - संयोजन पर आक्षेप

- (1) Can be taken at any stage of the proceedings/ प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर ली जा सकती है
- (2) should be taken at the earliest possible opportunity or shall be invalid / जल्द से जल्द संभव अवसर पर ली जाए या यह अमान्य हो जाएगी
- (3) can be taken in appeal or revision for the first time / पहली बार अपील या पुनरीक्षण में लिया जा सकता है
- (4) either (1) or (3)/ या तो (1) या (3)

Ans. [2]

21. Objection as to the place of suing / वाद की जगह को लेकर आपत्ति

- (1) can only be taken before the Court of first instance at the earliest possible opportunity / केवल जल्द से जल्द संभव अवसर पर न्यायलय से समक्ष पहली उपस्थिति के दौरान ही ली जा सकती है
- (2) can also be taken before the appellate Court for the first time / पहली बार अपीलीय न्यायलय के समक्ष ली जा सकती है
- (3) can also be taken before the Court of revision for the first time / पहली बार संशोधन न्यायलय के समक्ष ली जा सकती है
- (4) all of the above / उपरोक्त सभी।

Ans. [1]

Questions Paper with Linked provision is available on Linking App (Only for Paid Users)



Scan this
QR Code to
Linking Laws B10s

Linking Laws
Linking Laws Tansukh Sir
www.LinkingLaws.com
Get Subscription Now

Linking Laws is a Professional Institute provide
AI based Smart Preparation for
Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India
(UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)



22. On the retirement, removal or death of a next friend, under Order XXXII, Rule 10 of CPC, the suit is liable to be / वाद मित्र (नेक्स्ट फ्रेंड) की सेवानिवृत्ति, हटाए जाने या मृत्यु के पश्चात, सीपीसी के नियम 10 आदेश 32 के तहत वाद

- (1) stayed / पर रोक लगाई जाती है
- (2) dismissed / खारिज कर दिया जाता है
- (3) rejected / अस्वीकार कर दिया जाता है
- (4) either 1, 2 OR 3 / या (1), (2) और (3)

Ans. [1]

Criminal Procedure Code

54. Recording of pre-summoning evidence may be dispensed with under Section 200 of Cr.PC. / सम्मन पूर्व साक्ष्य की रिकॉर्डिंग को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत के साथ अस्वीकृत किया जा सकता है, यदि

- (1) If the complaint is supported by the affidavit of the complainant / शिकायत, शिकायतकर्ता के शपथ पत्र द्वारा समर्थित है
- (2) If the complaint is made in writing by a public servant in the discharge of his official duties / यदि शिकायत, एक लोक सेवक द्वारा लिखित रूप में अपने सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन में की जाती है
- (3) both I and 2 are correct / (1) और (2) दोनों सही हैं
- (4) only 1 is correct but 2 is incorrect / केवल (1) सही है, लेकिन (2) गलत है।

Ans. [2]

65. The offence of stalking upon second or subsequent conviction is / पीछा करना, दूसरे या उसके बाद के अपराध पर है

- (1) Non Cognizable and Bailable / गैर संज्ञेय और जमानती
- (2) Cognizable and Bailable / संज्ञेय और जमानती
- (3) Cognizable and Non-bailable / संज्ञेय और गैर जमानती
- (4) Non Cognizable and Non-bailable / गैर संज्ञेय और गैर जमानती

Ans. [3]

72. In a bailable offence bail is granted as a matter of right. / एक जमानती अपराध में अधिकार के रूप में जमानत प्रदान की जाती है

- (1) By the police officer / पुलिस अधिकारी द्वारा
- (2) By the Court / न्यायालय द्वारा
- (3) Both by the police officer and the Court / पुलिस अधिकारी और न्यायालय, दोनों द्वारा
- (4) either (1) or (2) / या तो 1 और या फिर 2

Ans. [3]

73. A proclaimed person whose property has been attached can claim the property or the sale proceeds on appearance / एक वांछित व्यक्ति, जिसकी घोषित संपत्ति की कुर्की कर दी गई है, संपत्ति या फिर बिक्री से प्राप्त आय का दावा कर सकता है, यदि वह उपस्थित होता है

- (1) within 6 months of attachment / कुर्की होने के 6 महीने के भीतर
- (2) within 2 years of attachment / कुर्की होने के 2 वर्ष के भीतर
- (3) within 3 years of attachment / कुर्की होने के 3 वर्ष के भीतर
- (4) within 1 year of attachment / कुर्की होने के 1 वर्ष के भीतर

Ans. [2]

74. The question whether a Statement was recorded in the course investigation is a / सवाल कि क्या कथन अन्वेषण के दौरान दर्ज किया गया है एक

- (1) question of law / कानून का सवाल है
- (2) question of fact / तथ्यों का सवाल है
- (3) mixed question of law and fact / कानून और तथ्यों का मिश्रित सवाल है
- (4) question of law or of fact depends on facts and circumstances / कानून का या तथ्यों का, यह निर्भर करेगा तथ्यों और परिस्थितियों पर।

Ans. [2]

75. Where the police submits a final report under Section 173 (2) of CrPC for dropping of proceedings to a Magistrate, the Magistrate / जहां पुलिस दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (2) के तहत कार्रवाई समाप्त करने को लेकर, दंडाधिकारी के समक्ष अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें तो दंडाधिकारी

- (1) may accept the same / उसे स्वीकार कर सकता है
- (2) may reject the same / उसे अस्वीकार कर सकता है
- (3) may reject the same and order further investigation / उसे अस्वीकार कर आगे की अन्वेषण के आदेश दे सकता है
- (4) any of the above / ऊपर का कोई भी

Ans. [4]

76. The orders under Section 125 of CrPC are / दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत आदेश हैं

- (1) summary in nature but finally determine the rights and obligations of the parties / प्रकृति में सारांश में है, लेकिन अंततः संबद्ध समूहों के अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण करता है
- (2) summary in nature and do not finally determine the rights and obligations of the parties which are to be finally determined by a civil Court / प्रकृति में सारांश में है, लेकिन अंत में संबद्ध समूहों के अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण नहीं करता, जिसे कि बाद में व्यवहार न्यायालय निर्धारित करता है
- (3) Substantive in nature and finally determine the rights and obligations of the parties. / प्रकृति में ठोस है, लेकिन अंततः संबद्ध समूहों के अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण करता है

Questions Paper with Linked provision is available on Linking App (Only for Paid Users)



Scan this
QR Code to
Linking Laws B10s

Linking Laws
Linking Laws Tansukh Sir
www.LinkingLaws.com
Get Subscription Now

Linking Laws is a Professional Institute provide
AI based Smart Preparation for
Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India
(UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)



- (4) Substantive in nature and are not Subject to determination of a right of the parties by a civil Court. / प्रकृति में ठोस है और एक व्यवहार न्यायालय द्वारा पार्टियों के अधिकार के निर्धारण के अधीन नहीं हैं

Ans. [2]

85. In a cognizable case under IPC, police have the / भारतीय दंड संहिता के तहत एक संज्ञेय मामले में पुलिस को

- (1) Authority to arrest a person without warrant / वारंट के बिना एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है
- (2) Authority to investigate the offence without permission of the Magistrate / बिना न्यायाधिकारी की अनुमति के, अपराध की अन्वेषण करने का अधिकार है
- (3) Both (1) or (2) / दोनों (1) और (2)
- (4) Either (1) or (2) / या तो (1) या (2)

Ans. [3]

86. During investigation a search can be conducted without warrant by / अन्वेषण के दौरान, वारंट के बिना खोज का कार्य आयोजित किया जा सकता है

- (1) any Police Officer / किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा
- (2) by the investigating officer / अन्वेषण अधिकारी द्वारा
- (3) Both (1) and (2) / दोनों (1) और (2)
- (4) either (1) or (2) / या तो (1) या फिर (2)

Ans. [3]

87. Committal proceedings under Sec. 209 of CrPC are in the nature of / दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 209 के तहत प्रतिबद्ध कार्यवाही की प्रकृति है

- (1) aid in investigation / अन्वेषण में सहयोगी
- (2) inquiry / जांच
- (3) trial / विचारण
- (4) either inquiry or trial / या तो जांच या विचारण

Ans. [2]

Indian Evidence Act

51. A retracted confession- / एक स्वीकारोक्ति, जिस पर बाद में मुकरा गया हो

- (1) can be solely made the basis of conviction/ केवल दोषसिद्धि आधार बनाया जा सकता है
- (2) cannot be solely made the basis of conviction/ केवल दोषसिद्धि आधार नहीं बनाया जा सकता है
- (3) cannot be solely made the basis of the same is conviction corroborated unless/ केवल दोषसिद्धि आधार नहीं बनाया जा सकता है, जब तक कि उसकी पुष्टि न हो
- (4) both a and c are correct / दोनों और सही हैं।

Ans. [3]

52. A confession to be inadmissible under Section 25 of the Act / अधिनियम की धारा 25 के तहत एक स्वीकारोक्ति अस्वीकार्य करने के लिए इस

- (1) must relate to the same crime for which offender is charged / जिसके लिए अपराधी पर आरोप लगाया है, उसी अपराध से संबंधित होना चाहिए
- (2) may relate to the same crime for which offender is charged / उसी अपराध के लिए, जिसके लिए अपराधी का आरोप लगाया है, से संबंधित हो सकती है
- (3) must relate to another crime / किसी अन्य अपराध से संबंधित होना चाहिए
- (4) none of the above/ उपरोक्त में से कोई भी नहीं।

Ans. [3]

53. An unjustified and unexplained long delay on the part of the Investigating Officer in recording the Statement of a material witness would render the evidence of such witness / एक महत्वपूर्ण साक्षी का कथन दर्ज करने की अन्वेषण अधिकारी की और से अनुचित और अस्पष्टिकृत लम्बी देरी ऐसे साक्षी के साक्ष्य को प्रस्तुत कर देगी

- (1) Unreliable / अविश्वसनीय
- (2) Inadmissible / अस्वीकार्य
- (3) Inadmissible and unreliable / अस्वीकार्य और अविश्वसनीय
- (4) None of the above / उपरोक्त में से कोई नहीं

Ans. [1]

70. Indian Evidence Act applies to / भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है

- (1) Proceedings before Tribunals / अधिकरणों के समक्ष कार्यवाही में
- (2) Proceedings before the arbitrator / मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही में
- (3) Judicial proceedings in Court / न्यायालय में न्यायिक कार्यवाही
- (4) All of the above / उपरोक्त सभी।

Ans. [3]

71. Fact in issue means- / विवाधक तथ्यों का आशय है-

- (1) Fact, existence or non existence of which is admitted by the parties / तथ्य, अस्तित्व या गैर अस्तित्व में हैं, जिन्हें कि पक्षों द्वारा स्वीकार किया जाता है
- (2) Fact, existence or non existence of which is disputed by the parties / तथ्य, अस्तित्व या गैर अस्तित्व में हैं, जिनमें कि पक्षों का विवाद है
- (3) Fact, existence or non existence of which is not disputed by the parties / तथ्य, अस्तित्व या गैर अस्तित्व में हैं, जिनमें कि पक्षों का विवाद नहीं है
- (4) All the above / उपर्युक्त सभी


Ans. [2]

81. Necessity rule as to admissibility of evidence is applicable when the maker of a Statement / साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए आवश्यकता नियम तब लागू होता है जब कथन देने वाला

Questions Paper with Linked provision is available on Linking App (Only for Paid Users)



Scan this
QR Code to
Linking Laws B10s

 **Linking Laws**
 **Linking Laws Tansukh Sir**
 www.LinkingLaws.com
 **Get Subscription Now**

Linking Laws is a Professional Institute provide
AI based Smart Preparation for
Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India
(UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)



- (1) is dead or has become incapable of giving evidence/ मृत है या साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है
- (2) is a person who can be found but his attendance cannot be procured without unreasonable delay or expenses / एक व्यक्ति जो खोजा तो जा सकता है, लेकिन उसकी उपस्थिति अनुचित देरी या खर्च के बिना सुनिश्चित नहीं की जा सकती
- (3) is a person who cannot be found / एक व्यक्ति जो खोजा नहीं जा सकता है
- (4) all of the above / उपर्युक्त सभी।

Ans. [4]

82. Secondary evidence of a document means / एक दस्तावेज के द्वितीयक साक्ष्य का आशय है ?

- (1) Copies of the document / दस्तावेज की प्रतियां
- (2) oral account of the contents of the documents/ दस्तावेजों की सामग्री का मौखिक विवरण
- (3) Both (1) and (2) / दोनों (1) और (2)
- (4) none of the above / उपरोक्त में से कोई भी नहीं

Ans. [3]

83. A Will is required to be proved by calling at least one attesting witness / किसी वसीयत को साबित करने के लिए आवश्यक है कि कम से कम एक अनुप्रमाणित करने वाले साक्षी को बुलाया जाए

- (1) when it is registered/ जब यह पंजीकृत हो
- (2) when it is unregistered / जब यह अपंजीकृत हो
- (3) when it is admitted / जब इसे स्वीकार किया जा रहा हो
- (4) All of the above / उपरोक्त सभी।

Ans. [1]

84. Any person in Section 106 of Evidence Act refers to / साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में कोई भी व्यक्ति संदर्भित किया जाता है

- (1) a party to the suit / वाद के लिए संबद्धित पक्ष हो
- (2) a stranger to the suit / वाद के लिए असंबद्धित पक्ष हो
- (3) a person who is not a party to the suit but interested in the outcome of the suit / एक व्यक्ति जो वाद के लिए संबंधित पक्ष तो नहीं है, लेकिन इसके परिणाम में उसकी दिलचस्पी है
- (4) all of the above / उपरोक्त सभी

Ans. [1]

Arbitration & Conciliation Act

1. The conciliation proceedings- / सुलह प्रक्रिया है-

- (1) Can be used as evidence in any judicial proceedings. / किसी भी न्यायिक कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है।
- (2) Can be used as evidence only in Arbitral proceedings. / केवल मध्यस्थ कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है।

- (3) Can be used as evidence only on the discretion of the judge or arbitrator./ केवल जज या मध्यस्थ के विवेक पर साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है।
- (4) Cannot be used as evidence in any judicial or arbitral proceedings. / किसी भी न्यायिक या मध्यस्थता कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल नहीं की जा सकती।

Ans. [4]

30. The present Arbitration and Conciliation Act of 1996 is based on- / वर्तमान 1996 का मध्यस्थता और सुलह अधिनियम पर आधारित है

- (1) Constitution of India / भारत के संविधान पर
- (2) Supreme Court of India guidelines / भारत के उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों पर
- (3) European Commercial Arbitration procedure. / यूरोपीय वाणिज्यिक मध्यस्थता प्रक्रिया पर
- (4) Uncitral/ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग पर (यूनिस्ड्रल)

Ans. [4]

33. The provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 have to be interpreted being uninfluenced by the principles underlying the 1940 Act. This observation was laid down in -/ मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधानों की व्याख्या 1940 अधिनियम के अंतर्निहित सिद्धांतों से अप्रभावित रह कर की जाना चाहिए। यह टिप्पणी की गई

- (1) M.M.T.C. Ltd vs. Sterlite Industries (India) Ltd./ एमएमटीसी लिमिटेड बनाम स्टरलाइट उद्योग (इंडिया) लिमिटेड
- (2) Sunderam Finance Ltd. vs. N.E.P.C. Ltd./ सुंदरम फाइनेंस लि बनाम वीएनईपीसी लिमिटेड
- (3) Olympus Superstructures Pvt. Ltd. vs. Meera Vijay / ओलंपस सुपरस्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड विरुद्ध मीरा विजय
- (4) Orma Impex Pvt. Ltd. vs. Nissari Pvt. Ltd. / ओरमा इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम निसारी प्राइवेट लिमिटेड मामले में

Ans. [2]

100. Which is an incorrect Statement? / इनमें से कौन सा गलत बयान है

- (1) An Arbitral award is a contract. / मध्यस्थता निर्णय एक संविदा है।
- (2) An Arbitral award must be in writing and signed / मध्यस्थता निर्णय लिखित में होकर, हस्ताक्षरित होना चाहिए
- (3) An Arbitral award included an interim award./ मध्यस्थता निर्णय में एक अंतरिम निर्णय भी शामिल है
- (4) None of the above / उपरोक्त में से कोई नहीं।

Ans. [1]

Professional Ethics & Cases of Professional Misconduct Under Bar Council of India Rules

29. The Supreme Court held in V.C. Rangadurai vs. D. Gopalan that an advocate who has been disbarred

Questions Paper with Linked provision is available on Linking App (Only for Paid Users)



Scan this QR Code to Linking Laws BLOs

Linking Laws
Linking Laws Tansukh Sir
www.LinkingLaws.com
Get Subscription Now

Linking Laws is a Professional Institute provide AI based Smart Preparation for Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India (UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)



or suspended from practice must prove after expiration of a reasonable length of time that, / वी.सी. रंगदुराई बनाम डी. गोपालन के मामले में आयोजित सुप्रीम कोर्ट- एक वकील जिसे निलंबित या वकालत करने से वंचित किया गया उसे उचित अवधि की समाप्ति के बाद यह साबित करना होगा कि

- (1) He appreciates the insignificance of his dereliction / वह अपने कर्तव्य त्यागने की निरर्थकता की सराहना करता है।
- (2) He has lived a consistent life of poverty and integrity/ उसने गरीबी और सच्चाई के संगत जीवन बिताया है।
- (3) He possesses the good character necessary to guarantee uprightness and honour in his professional dealings/ उसके पास व्यवसाय संबंधी व्यवहार के लिये जरूरी नेकी और मान की गारंटी दे सके ऐसा अच्छा चरित्र है।
- (4) The burden is on the applicant to establish that he entitled to resume the privilege of practicing law without restrictions./ यह सिद्ध करने का भार निवेदक का है कि वह बिना प्रतिबंध के वकालत शुरू करने के विशेष अधिकार के योग्य है।

Ans. [3]

43. State Bar Council under the provisions of Section 35 of the Advocates Act, 1961 has the authority to / अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 35 के प्रावधानों के तहत राज्य बार काउंसिल को अधिकार है कि वह -

- (1) Reprimand the advocate / वकील को फटकार लगाए
- (2) Suspend the advocate from practice for such period of time as it may deem fit / ऐसी समयावधि के लिए, जो वह उचित समझे अभ्यास से अधिवक्ता को निलंबित करे
- (3) Remove the name of the advocate from the State roll of advocates/ अधिवक्ताओं के राज्य रोल से अधिवक्ता का नाम हटाये
- (4) All of these / उपरोक्त सभी

Ans. [4]

44. Which of the following is untrue. regarding qualification for a person to be admitted on the State rolls maintained by State Bar Councils / राज्य बार काउंसिल द्वारा पोषित राज्य सूचियों में शामिल होने के लिए निम्न में से क्या सही नहीं है-

- (1) The minimum age of requirement is 21 years./ न्यूनतम आयु आवश्यकता 21 वर्ष हो
- (2) He must be an Indian Citizen / वह एक भारतीय नागरिक हो
- (3) He must not have been convicted of an offence involving moral turpitude / वह नैतिक अधमता सहित किसी अपराध का दोषी नहीं पाया गया हो
- (4) They must not have been convicted of an offence under the provisions of the Untouchability (Offences) Act, 1958 / वह अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम,

1958 के प्रावधानों के तहत किसी अपराध का दोषी नहीं पाया गया हो

Ans. [2]

99. The Bar Council of India Rule which stipulated that persons aged 45 years and above could not be enrolled as advocates was struck down by the Supreme Court in / बार काउंसिल ऑफ इंडिया का नियम जिसने निर्धारित किया की 45 साल और उसके उपर के व्यक्तियों को वकील के रूप में नामांकित नहीं किया जा सकता उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा में हटा दिया गया।

- (1) In E. S. Reddi vs. Bar Council of India / ई. एस. रेड्डी बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया
- (2) Indian Council of Legal Aid and Advice vs. Bar Council of India/ इंडीयन काउंसिल ऑफ लिगल एड बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया
- (3) P. Shanmugam vs. Bar Council of India/ पी. शानमुगम बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया
- (4) Legal Committee vs. Bar Council of India./ लिगल कमेटी बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया

Ans. [2]

Family Law

27. Onus to prove reasonable excuse for withdrawal from the Society of the other is on/ सोसायटी से हटाने के लिए का उचित बहाना साबित करने का दायित्व दुसरे का है

- (1) Petitioner / याचिकाकर्ता
- (2) Respondent / प्रतिवादी
- (3) Both (1) and (2) / (1) और (2) दोनों
- (4) Either (1) or (2) / या तो (1) या (2)

Ans. [2]

97. A disqualified person / heir/ एक अयोग्य घोषित व्यक्ति / वारिस

- (1) Transmits an interest to his or her own heir / अपने वारिस को संपत्ति दे देता या देती है।
- (2) Transmits no interest to his or her own heir / अपने वारिस को संपत्ति नहीं देता या देती है।
- (3) May or may not transmit an interest to his or her own heir as per the discretion of the Court / अदालत के निर्णय के अनुसार अपने वारिस, को संपत्ति दे या नहीं दे सकता या सकती है।
- (4) May only transmit an interest to his or her own heir with the consent of the other heirs. / केवल अन्य वारिसों की सहमति से ही अपने वारिस को संपत्ति दे सकता या सकती है।

Ans. [2]

Company Law

15. How is the net worth of a foreign Company calculated for the purpose of Corporate Social

Questions Paper with Linked provision is available on Linking App (Only for Paid Users)



Scan this QR Code to Linking Laws B10s

Linking Laws
Linking Laws Tansukh Sir
www.LinkingLaws.com
Get Subscription Now

Linking Laws is a Professional Institute provide AI based Smart Preparation for Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India (UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)



Responsibility? / कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के उद्देश्य से किसी विदेशी कंपनी की निवल संपत्ति की गणना कैसे की जाती है?

- (1) The networth will be calculated as per Section 198 of Companies Act, 2013 / कंपनी के शुद्ध मूल्य का हिसाब कंपनियों के अधिनियम 2013 की धारा 198 के अनुसार लगाया जाता है।
- (2) It shall be calculated as per Section 197 of the Companies Act, 2013 / यह हिसाब कंपनियों के अधिनियम 2013 की धारा 197 के अनुसार लगाया जाएगा।
- (3) It shall be calculated as per Section 197 and Section 381 of the Companies Act, 2013 / यह हिसाब कंपनियों के अधिनियम 2013 की धारा 197 और धारा 381 के अनुसार लगाया जाएगा।
- (4) It shall be calculated as per Section 198 and Sec. 381 of Companies Act, 2013./ यह हिसाब कंपनियों के अधिनियम 2013 धारा 198 और धारा 381 के अनुसार लगाया जाएगा।

Ans. [4]

17. Which of the following actions can be taken by a Registrar under Section 4 (5) of the Companies Act, 2013?/ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 4(5) एक पंजीयक द्वारा कौन सी कार्रवाई की जा सकती -

- (1) He can direct the Company to change its name within a period of 6 months after passing an ordinary resolution / वह कंपनी को एक साधारण प्रस्ताव पारित होने के बाद, 6 महीने की अवधि के भीतर अपना नाम बदलने के लिए निर्देशित कर सकता है
- (2) Take action for striking off the name of the Company from the registrar of Companies / वह कंपनी का नाम, कंपनी रजिस्ट्रार से काटने की कार्रवाई कर सकता है
- (3) Order winding up of the Company on his own accord / स्वयं के समझौते पर कंपनी को बंद करने का आदेश दे सकता है,
- (4) All of these / इन सभी के निर्देश दे सकता है

Ans. [4]

31. Who among the following is authorized to issue regarding shelf prospectus / निम्नलिखित में से कौन शेल्फ प्रोस्पेक्टस के संबंध में को जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है

- (1) SEBI / सेबी
- (2) Central Government / केन्द्रीय सरकार
- (3) Company Law Board regulations / कंपनी लॉ बोर्ड विनियमन
- (4) National Company Law Tribunal / राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण

Ans. [1]

34. Which of the following services cannot be provided to the Company by an auditor appointed, under the provisions of the Companies Act, 2013/ एक लेखा परीक्षक जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत नियुक्त

किया गया हो, निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी सेवा कंपनी को प्रदान नहीं कर सकता हैं

- (1) Internal Audit / आंतरिक लेख परीक्षा
- (2) Actuarial services / बीमांकिक सेवाएं
- (3) Managerial Services / प्रबंधकीय सेवा
- (4) All of these / उपरोक्त सभी।

Ans. [4]

96. Which of the following Companies will have to constitute Corporate Social responsibility Committee under the Companies Act, 2013/ चे दी गयी कंपनियों में से कौन सी कंपनी को कंपनियों के अधिनियम, 2013 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी की समिति का गठन करना होगा?"

- (1) A Company having a net profit of 2.5 cores in a financial year, a net worth of 300 crores and a turnover of rupees 800 crore / एक कंपनी जिसके एक वित्तीय वर्ष का शुद्ध लाभ 2.5 करोड़ रुपये का शुद्ध मूल्य 300 करोड़ रुपये का और कारोबार 800 करोड़ रुपये का हो।
- (2) A Company having a net profit of 3 cores, in a financial year, a net worth of 300 crores and a turnover of rupees 600 crore / एक कंपनी जिसके एक वित्तीय वर्ष का शुद्ध लाभ 3 करोड़ रुपये का शुद्ध मूल्य 300 करोड़ रुपये का और कारोबार 600 करोड़ रुपये का हो।
- (3) A Company having a net profit of 5 crores or more, a net worth of 500 crores and a turnover of rupees 1000 crore or more / एक कंपनी जिसके एक वित्तीय वर्ष का शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपये से ज्यादा, शुद्ध मूल्य 500 करोड़ रुपये और कारोबार 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा हो।
- (4) A Company having a net profit of 5 crores or more, a net worth of 500 crores and a turnover of rupees 5000 crore or more / एक कंपनी जिसके एक वित्तीय वर्ष का शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपये से ज्यादा, शुद्ध मूल्य 500 करोड़ रुपये और कारोबार 5000 करोड़ रुपये से ज्यादा हो।

Ans. [3]

Environment Pro. Act

6. Which of the following is a function of Central Pollution Control Board under the provisions of Section 16 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981? / वायु (निवारण) और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 16 के प्रावधानों के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास कौन सी जिम्मेदारी है?

- (1) To carry out and sponsor investigation and research relating to problems of pollution and prevention, control or abatement of pollution./ प्रदूषण और इसकी रोकथाम, नियंत्रण और बढ़ावा देने संबंधी समस्याओं की अन्वेषण और अनुसंधान को अंजाम देना और प्रायोजित करना।
- (2) To improve the quality of air / हवा की गुणवत्ता में सुधार करना।

Questions Paper with Linked provision is available on Linking App (Only for Paid Users)



Scan this
QR Code to
Linking Laws B10s

Linking Laws
Linking Laws Tansukh Sir
www.LinkingLaws.com
Get Subscription Now

Linking Laws is a Professional Institute provide
AI based Smart Preparation for
Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India
(UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)



- (3) Both (1) and (2) / (1) और (2) दोनों
(4) neither (1) and (2) / (1) और (2) दोनों नहीं।

Ans. [3]

7. The destruction of fish by use of explosive or by poisoning the water is prohibited by / विस्फोटक के इस्तेमाल से या पानी को जहरीला बनाकर मछलियों को नष्ट करना प्रतिबंधित है

- (1) Environment (Protection) Act, 1986 / पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
(2) The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 / जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
(3) Indian Fisheries Act, 1897 / भारतीय मत्स्य अधिनियम, 1897
(4) The National Green Tribunal Act, 2010 / राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010.

Ans. [3]

32. Which of the following is not included in the definition of cattle as given under the Indian Forest Act, 1927 / भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा मवेशी शामिल नहीं है

- (1) Rams / मेढ
(2) Kids / मेमना
(3) Kitten / बिल्ली का बच्चा
(4) None of these / इनमें से कोई नहीं।

Ans. [3]

35. Under the Wild Life (Protection) Act, 1972, any person who teases an animal in a zoo maybe punished / वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत, कोई भी व्यक्ति जो कि चिड़ियाघर में किसी जानवर को छेड़ता है उसे दंडित किया जा सकता है

- (1) with fine with may extend to 5000 / जुर्माना, जिसकी राशि बढ़ाकर 5000 रूपए तक हो सकती है
(2) with imprisonment which may extend upto 1 year / कारावास, जिसे 1 साल तक विस्तारित किया जा सकता है
(3) Both (1) and (2) / (1) और (2) दोनों
(4) Neither (1) or (2) / (1) और (2) दोनों नहीं।

Ans. [4]

Cyber Law

2. The Serious Fraud Investigation Office / गंभीर धोखाधड़ी अन्वेषण कार्यालय

- (1) Takes up cases suo motto / स्वतः संज्ञान लेकर मामलों पर कार्रवाई करता है
(2) Takes up cases for investigation on the basis of application made by the people concerned / संबंधित व्यक्तियों द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर अन्वेषण के लिए कार्रवाई करता है

- (3) Takes up cases for investigations referred to it by Central Government / केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित किए गए मामलों में अन्वेषण संबंधी कार्रवाई करता है
(4) All of the above / उपरोक्त सभी।

Ans. [4]

23. In India which of the following authorities has the power to block websites? / भारत में निम्नलिखित में से वेबसाइटों को ब्लॉक करने की शक्ति किसका प्राधिकार है?

- (1) CERT-in / सीईआरटी-इन
(2) MCIIPC / एमसीआईआईपीसी
(3) C-DAC / सी-डैक
(4) Ministry of IT / सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

Ans. [4]

61. The Controller of Certifying Authorities in India must maintain a database of the disclosure records of / भारत में प्रमाणन प्राधिकरणों के नियंत्रक को किनके प्रकटीकरण रिकॉर्ड का विवरण (डेटाबेस) बनाए रखना चाहिए "

- A. Certifying Authority / प्रमाणन प्राधिकारी
B. Cross Certifying Authority / क्रॉस प्रमाणन प्राधिकरण
C. Foreign Certifying Authority / विदेशी प्रमाणन प्राधिकरण
(1) A and B
(2) B and C
(3) C and A
(4) A, B and C

Ans. [4]

62. Under Section 37 of the IT Act, 2000, the certifying authority can suspend the digital signature certificate if / सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 37 के तहत, प्रमाणन प्राधिकरण डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र निलंबित कर सकते हैं, यदि -

- A. The subscriber is found guilty of malpractice / ग्राहक कदाचार का दोषी पाया जाता है
B. The subscriber is involved in cyber terrorism / ग्राहक साइबर आतंकवाद में शामिल है।
C. The subscriber requests for the same / इन्हीं के लिए ग्राहक अनुरोध करता है
D. In public interest / लोक के हित में
(1) A and B
(2) B and C
(3) C and D
(4) D and A

Ans. [3]

63. In the cases before Cyber Appellate Tribunal, the appellant / साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष मामलों में, अपीलार्थी

Questions Paper with Linked provision is available on Linking App (Only for Paid Users)



Scan this
QR Code to
Linking Laws BLOs

 Linking Laws
 Linking Laws Tansukh Sir
 www.LinkingLaws.com
 Get Subscription Now

Linking Laws is a Professional Institute provide
AI based Smart Preparation for
Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India
(UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)



- (1) Cannot appear in person without a legal practitioner / एक कानूनी पेशेवर के बिना व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकता
- (2) Cannot authorize a legal practitioner to appear on his behalf / किसी कानूनी पेशेवर को स्वयं की ओर से उपस्थित होने के लिए अधिकृत नहीं कर सकता
- (3) Cannot authorize his officer to appear on his behalf / अपने अधिकारी को स्वयं की ओर से उपस्थित होने के लिए अधिकृत नहीं कर सकता
- (4) Cannot authorize his relative who is neither his officer nor a legal practitioner to appear on his behalf. / किसी रिश्तेदार को, जो न तो कानूनी पेशेवर है और न ही उसका अधिकारी है, को स्वयं की ओर से उपस्थित होने के लिए अधिकृत नहीं कर सकता।

Ans. [4]

78. Which among the following is authorized under the Information Technology Act, 2000 to prescribe the security procedures and practices for the purpose of Sections 14 and 15 of the Act? / निम्नलिखित में से कौन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 14 और 15 के तहत सुरक्षा प्रक्रियाओं और प्रथा जारी करने के लिए अधिकृत है?

- (1) Central Government/ केन्द्रीय सरकार
- (2) State Government / राज्य सरकार
- (3) Certifying authority / प्रमाणन अधिकारी
- (4) Issuing authority / जारी करने वाले प्राधिकारी

Ans. [1]

Labour & Industrial Law

25. Which of the following can be considered retrenchment under the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947? / औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के तहत निम्न में से किसे छंटनी माना जा सकता है ?

- (1) Termination due to ill-health / खराब स्वास्थ्य के कारण नौकरी से बर्खास्तगी
- (2) Abandonment of job by an employee/ किसी कर्मचारी द्वारा नौकरी का परित्याग
- (3) Termination on account of reaching the age of superannuation / सेवानिवृत्ति की उम्र तक पहुँचने के कारण सेवा समाप्ति
- (4) None of these / इनमें से कोई नहीं

Ans. [4]

26. Which of the following Statement holds true regarding imprisonment under the provisions of Section 14 (3) of the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 / बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 14 (3) के प्रावधानों के तहत कारावास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है

- (1) It may extend to one year. / इसे एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है

- (2) It may extend to two years. / इसे दो वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है
- (3) It may extend to six months. / इसे छह महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है
- (4) It may extend to one month / इसे एक महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है

Ans. [4]

39. The provisions of do not apply to trade unions registered under the Provisions of Trade Union Act, 1926. / ये प्रावधान ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत ट्रेड यूनियनों पर लागू नहीं होते हैं

- (1) The Co-operative Societies Act, 1912 / सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1912
- (2) The Companies Act, 1956/ कंपनी अधिनियम, 1956
- (3) Both (1) and (2) / दोनों (1) और (2)
- (4) Neither (1) nor (2) / न तो (1) और न ही (2)

Ans. [3]

47. Under the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, the appropriate Government can by order in writing/ औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के तहत, उपयुक्त सरकार लिखित में आदेश के माध्यम से

- (1) Refer the dispute to a Board for promoting a settlement of the dispute / विवाद के समाधान को बढ़ावा देने के लिए विवाद को किसी मंडल को सौंप दे
- (2) Refer any matter appearing to be relevant to the dispute to a Court for inquiry / विवाद के लिए सुसंगत होने वाले किसी मुद्दे को जांच के लिए किसी न्यायालय को सौंप दे
- (3) Both (1) and (2) / दोनों (1) और (2)
- (4) neither (1) nor (2) / न तो (1) और न ही (2)

Ans. [3]

48. Which of the following Statement is true for loss of confidence by management in the workman? / निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्रमिक में प्रबंधन द्वारा विश्वास की हानि के संबंध में सच है ?


- (1) Even when dismissal or discharge is held to be wrongful, the Court may not yet order reinstatement if the employer is able to establish that the workman held a position of trust and there was loss of confidence. / जब बर्खास्तगी या हटाया जाना गलत तरीके से होना पाया जाए और फिर भी न्यायालय बहाली का आदेश जारी न करे, यदि नियोजक यह स्थापित करने में सक्षम है कि कर्मचारी विश्वास के पद पर कार्य कर रहा था और अब कर्मचारी पर विश्वास खो दिया है
- (2) Loss of confidence may also be a ground for discharge simpliciter of the workman / विश्वास की कमी भी कर्मकार को कार्यमुक्त करने का आधार हो सकता है
- (3) Both (1) and (2) / दोनों (1) और (2)
- (4) neither (1) nor (2) / न तो (1) और न ही (2)

Ans. [3]

Questions Paper with Linked provision is available on Linking App (Only for Paid Users)



Scan this
QR Code to
Linking Laws BLOs

 **Linking Laws**
 **Linking Laws Tansukh Sir**
 www.LinkingLaws.com
 **Get Subscription Now**

Linking Laws is a Professional Institute provide
AI based Smart Preparation for
Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India
(UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)



67. Under the provisions of the Trade Unions Act, 1926, any person who has attained the age of may be a member of a registered Trade Union subject to any rules of the Trade Union to the contrary. / कर्मचारी संगठन अधिनियम, 1926 के प्रावधानों के तहत किसी भी व्यक्ति ने, जिसने वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, एक पंजीकृत कर्मचारी संगठन का सदस्य हो सकता है बशर्ते का कोई नियम इसके कर्मचारी संगठन विपरीत न हो

- (1) 14 years
- (2) 15 years
- (3) 18 years
- (4) 21 years

Ans. [2]

Law Of Torts, M.V. Act and Consumer Protection Law

40. According to Salmond every legal right/ साल्मन्ड के अनुसार हर कानूनी अधिकार

- (1) Cannot be vested in a person/ एक व्यक्ति में स्थित नहीं किया जा सकता।
- (2) Is availed against a person upon whom lies the correlative duty / उस व्यक्ति के खिलाफ काम आता है जिसके उपर आपसी कर्तव्य पूरा करने का दायित्व है।
- (3) Cannot oblige the person bound to an act or omission in favour of the person entitled / एक हकदार व्यक्ति के पक्ष में उस व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकता जो किसी अधिनियम या चूक करने के लिये बंधा हो।
- (4) Cannot have a title / का एक शीर्षक नहीं हो सकता।

Ans. [2]

49. Under the provisions of the Consumer Protection Act, 1986, the period of limitation complaint before the Commission is for filing National / उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय आयोग के समक्ष शिकायत दाखिल करने की सीमा की अवधि है

- (1) 1 year from the date on which cause of action has arisen/ उस तारीख से 1 साल, जिस पर कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ हो
- (2) 2 year from the date on which cause of action has arisen / उस तारीख से 2 साल, जिस पर कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ हो
- (3) 3 year from the date on which cause of action has arisen / उस तारीख से 3 साल, जिस पर कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ हो
- (4) 4 year from the date on which cause of action has arisen / उस तारीख से 4 साल, जिस पर कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ हो

Ans. [2]

50. Grievous hurt under the Motor Vehicles Act, 1988 means' / मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत घोर उपहति का आशय है

- (1) Grievous hurt as defined in IPC / घोर उपहति, जो कि भारतीय दंड संहिता में परिभाषित है
- (2) Grievous hurt as defined in medical laws / घोर उपहति जो कि चिकित्सा कानून में परिभाषित है
- (3) Grievous hurt as detected by medical practitioner / घोर उपहति, जो कि चिकित्सक द्वारा पता लगाया जाता है
- (4) none of the above / उपरोक्त में से कोई भी नहीं।

Ans. [1]

68. Spurious goods under the provisions of the Consumer Protection Act, 1986 imply / उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत नकली सामान का अर्थ है

- (1) Such goods and services which are of poor quality. / ऐसी वस्तुएं और सेवा, जो कि घटिया गुणवत्ता के हैं
- (2) Such goods and services which are claimed to be genuine but they are actually not so/ ऐसी वस्तुएं और सेवा, जिनके वास्तविक होने का दावा तो किया जाता है लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता
- (3) Such goods and services which might be stolen in nature / ऐसी वस्तुएं और सेवा, जो चोरी की हो सकती हैं
- (4) Such goods and services which are not usable in nature / ऐसी वस्तुएं और सेवा, प्रयोग करने के योग्य नहीं हैं।

Ans. [2]

69. Who is liable to pay compensation in case of death or permanent disablement? / मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में मुआवजे का भुगतान करने के लिए कौन उत्तरदायी है?

- (1) Owner of the vehicle / वाहन का स्वामी
- (2) State Government / राज्य सरकार
- (3) Driver / चालक
- (4) Insurance Company / बीमा कंपनी।

Ans. [1]

79. The essential ingredient of the tort of negligence are / लापरवाही अपकृत्य का अनिवार्य अंग है

- (1) When one owes a duty of care towards the other. / जब कोई कर्मचारी, दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का कार्य करता है
- (2) When one commits a breach of that duty and/ जब कर्मचारी कर्तव्य का उल्लंघन करता है और
- (3) The other person suffers damage as a consequence thereof / दूसरा पक्ष, इस व्यक्ति के इन क्रियाकलापों के चलते क्षति उठाता है

Choose correct response for below / निम्न में से सही जवाब चुनें

- (1) None of them are essential ingredients/ इनमें से कोई भी आवश्यक तत्व नहीं हैं

Questions Paper with Linked provision is available on Linking App (Only for Paid Users)



Scan this QR Code to Linking Laws B10s

Linking Laws
Linking Laws Tansukh Sir
www.LinkingLaws.com
Get Subscription Now

Linking Laws is a Professional Institute provide AI based Smart Preparation for Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India (UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)



- (2) Only the first is an essential ingredient / केवल प्रथम अनिवार्य अंग है
- (3) All of them are essential ingredients / उपरोक्त सभी आवश्यक तत्व हैं
- (4) Even if the first is absent the tort of negligence is committed / यदि प्रथम अनुपस्थित है फिर भी लापरवाही का अपकृत्य घटित हुआ है।

Ans. [3]

80. Vicarious liability includes / प्रत्यधिकृत दायित्वों में शामिल है

- (1) Liability of the principal for the tort of his agent/ उसके प्रतिनिधि के अपकृत्य के लिए प्रमुख का दायित्व है
- (2) Liability of the master for the tort of his servant/ नौकर के अपकृत्य के लिए मालिक का दायित्व है
- (3) Liability of the partners for each other tort / एक दूसरे के अपकृत्यों के लिए भागीदारों का दायित्व है
- (4) all of the above/ उपरोक्त सभी

Ans. [4]

Law of Contract, Specific Relief, Property Laws, Negotiable Instrument Act,

14. If an instrument may be construed either as promissory note or bill of exchange, it is/ यदि किसी लिखत को वचनपत्र या विनिमय बिल के रूप में माना जा सकता है तो यह

- (1) a valid instrument / एक वैध साधन है
- (2) an ambiguous instrument / एक अस्पष्ट साधन है
- (3) a returnable instrument / एक वापसी योग्य साधन है
- (4) none of the above / उपरोक्त में से कोई भी नहीं।

Ans. [2]

38. What is true of perpetual injunction/ सतत निषेधाज्ञा के लिए क्या सच है

- (1) It is a judicial process / यह एक न्यायिक प्रक्रिया है
- (2) preventive in nature / यह प्रकृति में निवारक है
- (3) the thing prevented is a wrongful act/ किसी कार्य का गलत तरीके से रोका गया
- (4) all of the above / उपरोक्त सभी

Ans. [2]

55. Contract without consideration made in writing and registered and made on account of natural love and affection is / बिना प्रतिफल किए, लिखित में किया गया संविदा जो कि पंजीकृत किया गया जो कि प्राकृतिक प्यार और स्नेह के आधार पर किया गया है वह

- (1) void / शून्य
- (2) reasonable / उचित
- (3) valid / वैध
- (4) unenforceable / अप्रवर्तनीय

Ans. [3]

56. Under the Transfer of Property Act, 1882 / संपत्ति अधिनियम, 1882 के तहत स्थानांतरण

- (1) the salary of a public officer can be transferred/ एक लोक अधिकारी के वेतन को स्थानांतरित किया जा सकता है
- (2) the salary of a public officer cannot be transferred/ एक लोक अधिकारी के वेतन को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है
- (3) public office can be transferred/ सार्वजनिक कार्यालय स्थानांतरित किया जा सकता है
- (4) none of the above/ उपरोक्त में से कोई भी नहीं

Ans. [2]

57. Where a debt is transferred for the purpose of securing an existing or future debt, the debt so transferred, if or received by the transferor recovered by the transferee applicable first, in payment of cost of is such recovery. This is the provision of / जहां एक उधार स्थानांतरित किया जा रहा है, जिसका प्रयोजन मौजूदा या भविष्य में कर्ज हासिल करना है, यदि अंतरणकर्ता द्वारा प्राप्त किया जाता है या स्थानांतरण करने वाला इसे प्राप्त करता है तो इस तरह का स्थानांतरण, जो कि किया गया है, में वसूली की लागत का भुगतान प्रथम होगा। यह प्रावधान है

- (1) mortgaged debt/ बंधक ऋण
- (2) gift / दान
- (3) actionable claim / अनुयोज्य दावे
- (4) lease/ पट्टा संबंधी।

Ans. [1]

58. A suit under Section 6 of the Specific Relief Act can be brought by / विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 6 के तहत दावा किया जा सकता है

- (1) trespasser / अतिचारी द्वारा
- (2) a tenant holding over / किरायेदार द्वारा कब्जा
- (3) servant / नौकर
- (4) manager / प्रबंधक द्वारा

Ans. [2]

59. Injunction cannot be granted in a suit / एक दावा में निषेधाज्ञा की अनुमति नहीं दी जा सकती है"

- (1) in which the specific performance cannot enforced/ जिसमें विशिष्ट प्रदर्शन लागू नहीं कर सकते
- (2) for breach of negative contract to enforce specific contract / विशिष्ट संविदा लागू करने के लिए नकारात्मक अनुबंध का उल्लंघन
- (3) for declaration where the plaintiff is in possession / घोषणा के लिए जहां वादी का कब्जा है
- (4) neither 1, nor 2, nor 3/ न तो (1), न ही (2) न ही (3)


Ans. [1]

77. A contingent contract based on the uncertain events not specified happening within a fixed time under Section 35- / धारा 35 के तहत एक आपातक संविदा ,

Questions Paper with Linked provision is available on Linking App (Only for Paid Users)



Scan this QR Code to Linking Laws B10s

 **Linking Laws**
 **Linking Laws Tansukh Sir**
 www.LinkingLaws.com
 **Get Subscription Now**

Linking Laws is a Professional Institute provide AI based Smart Preparation for Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India (UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)



जो कि विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटनाओं के आधार पर है, यदि निश्चित समय के अंदर नहीं हो रहा है-

- (1) remains valid even if the event does not happen within that fixed time / भले ही घटना न हो, लेकिन संविदा उस निश्चित समयावधि के लिए वैध रहता है.
- (2) becomes void at the expiration of the time fixed / समय की समाप्ति पर संविदा शून्य हो जाता है
- (3) becomes void if the happening of that event becomes impossible before the expiry of time fixed. / शून्य हो जाता है, यदि समय की समाप्ति के पूर्व ही तय हो जाता है कि घटना का होना असंभव है
- (4) both (2) and (3) / दोनों (2) और (3)

Ans. [4]

88. Which is correct?/ कौन सा सही है

- (1) proposal + acceptance = promise / प्रस्थापना + प्रतिग्रहण = वायदा
- (2) promise + consideration = agreement/ वचन + प्रतिफल = करार
- (3) agreement + enforceability = contract / करार + प्रवर्तन = संविदा
- (4) all of the above / उपरोक्त सभी

Ans. [4]

89. Communication of acceptance is complete as against the proposer / प्रतिग्रहण का संचार प्रस्तावक के खिलाफ पूरा होता है

- (1) when it comes to the knowledge of the proposer/ जब यह प्रस्तावक के ज्ञान में आता है
- (2) when it is put in course of transmission to him so as to be out of power of the acceptor / जब यह उसके लिए संसूचना की प्रक्रिया में डाल दिया जाता है, ताकि प्रतिग्रहण के शक्ति के बाहर रहे
- (3) when the acceptance is communicated to the proposer / जब प्रतिग्रहण प्रस्तावक को संसूचना कर दी जाती है
- (4) all of the above / उपरोक्त सभी

Ans. [2]

90. In cases of general offer, for a valid contract/ एक वैध संविदा के लिए सामान्य प्रस्ताव के मामलों में

- (1) the acceptor need not have the knowledge of the offer / प्रतिग्रहण को प्रस्ताव के विवरण की जानकारी की आवश्यकता नहीं है
- (2) the acceptor must have the knowledge of the offer before acceptance by performance / प्रतिग्रह को प्रदर्शन से पहले प्रतिग्रहण के प्रस्ताव का ज्ञान होना चाहिए
- (3) the acceptor may acquire the knowledge of the offer after the performance of the condition for acceptance / स्वीकर्ता प्रतिग्रहण के लिए शर्त के प्रदर्शन के पश्चात प्रस्ताव का ज्ञान प्राप्त कर सकता है।
- (4) knowledge does not matter so long as the condition is performed with or without

knowledge / ज्ञान से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कार्य किसी जानकारी के साथ या बिना जानकारी के साथ किया जाए।

Ans. [2]

91. Under the provision of the Transfer of Property Act, 1882, the unborn person acquires vested interest on transfer for his benefit / संपत्ति स्थानांतरण अधिनियम, 1882 के प्रावधान के तहत, अजन्मा व्यक्ति अपने लाभ के लिए हस्तांतरण को प्राप्त करता है 1

- (1) upon his birth / अपने जन्म पर
- (2) 7 days after his birth / अपने जन्म के 7 दिनों के पश्चात
- (3) 12 days after his birth / अपने जन्म के 12 दिनों के पश्चात
- (4) no such provision is made / ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

Ans. [1]

92. Every transfer of immovable property made with intent to defeat or delay the creditors of the transferor shall be voidable/ अचल संपत्ति के प्रत्येक हस्तांतरण, जो कि अंतरणकर्ता के लेनदारों को पराजित करने या देरी करने के इरादे से होगा, शून्य कर दिया जाएगा जब

- (1) at the option of creditor so defeated or delayed/ लेनदार के विकल्प, जो कि पराजित हुआ है या देरी हुई है
- (2) at the option of debtor / ऋणी के विकल्प पर
- (3) at the option of Court / न्यायलय के विकल्प पर
- (4) none of the above / उपरोक्त में से कोई नहीं

Ans. [1]

93. Where co-judgment debtors are in the position of joint promisors, each is- / जहां सह-निर्णय देनदार संयुक्त वचनदाता की स्थिति में हैं, प्रत्येक

- (1) not jointly and severally liable to the decree holder / डिक्री धारक के लिए संयुक्त और पृथक रूप से उत्तरदायी नहीं
- (2) jointly and severally liable to the decree holder/ डिक्री धारक के लिए संयुक्त और पृथक रूप से उत्तरदायी
- (3) jointly liable to the decree holder only / केवल डिक्री धारक के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी
- (4) severally liable to the decree holder only/ केवल डिक्री धारक के लिए पृथक रूप से उत्तरदायी

Ans. [2]

94. At sight under Section 21 of the Negotiable Instruments Act, 1881 means / परक्राम्य प्रपत्र अधिनियम, 1881 की धारा 21 को संदर्भित किया जाता है

- (1) on presentation / प्रस्तुति पर
- (2) on demand / मांग पर
- (3) on coming into vision / दृष्टि में आने पर
- (4) none of the above / उपरोक्त में से कोई भी नहीं।

Ans. [2]

Questions Paper with Linked provision is available on Linking App (Only for Paid Users)



Scan this
QR Code to
Linking Laws BLOs

 Linking Laws
 Linking Laws Tansukh Sir
 www.LinkingLaws.com
 Get Subscription Now

Linking Laws is a Professional Institute provide
AI based Smart Preparation for
Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India
(UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)



98. In cases in which a specific act confers a discretionary power on an authority . / ऐसे मामले जिनमें कोई विशेष अधिनियम किसी सत्ता को अपने विवेक से फैसला लेने की शक्ति प्रदान करता हो उनमें 8

- (1) The Court can direct the manner in which the power is exercised / न्यायलय यह आदेश दे सकती है कि सत्ता का प्रयोग किस प्रकार होना चाहिए।
- (2) The Court can direct that the power be exercised in accordance with law/ न्यायलय यह आदेश दे सकती है कि सत्ता का प्रयोग कानून के अनुसार किया जाना चाहिए।
- (3) Both (1) and (2) / (1) और (2) दोनों
- (4) Neither (1) nor (2) / ना तो (1) ना (2)

Ans. [2]

Limitation Act

45. Time which has begun to run can be stopped in case of / समय जो बीतने लगा हों उसे के मामले में रोका जा सकता है।

- (1) Minority / अल्पसंख्यक
- (2) Insanity / पागलपन
- (3) Idiocy / मूर्खता
- (4) None of the above / उपरोक्त में से कोई भी नहीं

Ans. [4]

95. Section 5 of the Limitation Act applies to/ सीमा अधिनियम की धारा 5 -

- (1) Suits / वाद
- (2) Execution / निष्पादन
- (3) Election petitions / चुनाव याचिकाएँ के लिये लागू होती है
- (4) None of the above/ उपरोक्त में से कोई भी नहीं

Ans. [1]

International Law

10. International law is a weak law because / अंतर्राष्ट्रीय कानून एक कमजोर कानून है क्योंकि

- (1) It is not enforceable as such, it is not a law but a positive morality / यह उसकी तरह प्रवर्तनीय नहीं है, बल्कि यह एक कानून नहीं, एक सकारात्मक नैतिकता है
- (2) There is absence of compulsory dispute settlement mechanisms and independent system of sanctions / अनिवार्य विवाद निपटान तंत्र और प्रतिबंधों की स्वतंत्र प्रणाली का अभाव है
- (3) It only includes States as subjects / यह केवल राज्य को विषय के रूप में शामिल करता है
- (4) There is no dependable sources available/ कोई भरोसेमंद स्रोत उपलब्ध नहीं है।

Ans. [2]

11. Which of the following territories have been declared as Common Heritage of Mankind Territories? / निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को मानव जाति क्षेत्रों के लिए साझी विरासत के रूप में घोषित किया गया

- (A) Moon / चंद्रमा
- (B) High seas / गहरे समुद्र
- (C) Deep sea bed / प्रचंड समुद्री - लहरें
- (D) Antarctica / अंटार्कटिका

- (1) A, B and D
- (2) A and C
- (3) B, C, and D
- (4) B and D

Ans. [3]

12. Which of the following is not the objective of the United Nations /निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य नहीं है,

- (1) Maintenance of International peace and security / अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना
- (2) Ensuring respect for treaty' obligations / संधि दायित्वों के प्रति सम्मान सुनिश्चित करना
- (3) Establishment of democratic Governments throughout the world / दुनिया भर में लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना
- (4) Promotion of better standards of life / जीवन के बेहतर मानकों को बढ़ावा देना।

Ans. [3]

60. State practice for the formation of customary rule includes / प्रथागत नियम के गठन के लिए राज्य अभ्यास में शामिल है"

- A. State actions / राज्य कार्रवाई
- B. State claims / राज्य का दावा

- (1) only A / केवल (क)
- (2) only B / केवल (ख)
- (3) both A and B / क और ख दोनों
- (4) neither A nor B / न तो क न ही ख

Ans. [3]

Jurisprudence

28. Which of the following Statements hold true for adjudicatory bodies/ नीचे दिए गए वर्णनों में से कौन सा वर्णन एडज्यूकेटरी संस्थाओं के लिए सही है ?

- (1) Doctrine of Stare Decisis applies to them/ उन पर स्टेर डेसिसिस का सिद्धांत लागू होता है।
- (2) Doctrine of Res judicata does not apply to them/ उन पर रे जुडिकेट का सिद्धांत नहीं लागू होता है।
- (3) Inherent lack of jurisdiction in a Tribunal cannot be cured or created by the act of the parties/ एक न्यायाधिकरण में निहित अधिकार क्षेत्र की कमी को पक्षों के अधिनियम द्वारा बनाया या ठीक नहीं किया जा सकता।
- (4) None of the above/ उपरोक्त में से कोई भी नहीं।

Ans. [3]

Questions Paper with Linked provision is available on Linking App (Only for Paid Users)



Scan this QR Code to Linking Laws B10s

Linking Laws
Linking Laws Tansukh Sir
www.LinkingLaws.com
Get Subscription Now

Linking Laws is a Professional Institute provide AI based Smart Preparation for Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India (UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)



41. The binding force of precedent is destroyed or weakened by / मिसाल की बाध्यकारी शक्ति नष्ट या कमजोर हो जाती है

- (1) Public opinion / जनता की राय
- (2) Abrogated decision / निराकृत निर्णय
- (3) Res judicata / रेस जुडिकाटा
- (4) Lis pendens / लिस पेंडेन्स

Ans. [2]

GK

37. Droit des Gens (Law of Nations) 1758 was written by / ड्रॉइट डेस जीन्स (राष्ट्र की विधि) 1758 किसके द्वारा लिखी गई है

- (1) Cornelius van Bynkershoek / कॉर्नेलियस वैन बेनकेरशोएक
- (2) Emerich de Vattel / एमिरिच डी वाट्टेल
- (3) Richard Zouch / रिचर्ड जूक
- (4) Jean Bodin / जीन बोडिन

Ans. [2]



Questions Paper with Linked provision is available on Linking App (**Only for Paid Users**)



Scan this
QR Code to
Linking Laws B10s

 **Linking Laws**
 [Linking Laws Tansukh Sir](#)
 www.LinkingLaws.com
 [Get Subscription Now](#)

Linking Laws is a Professional Institute provide
AI based Smart Preparation for
Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India
(UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)